

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं:-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

क्रमांक/एफ-3/129/378893/0017/10

दिनांक: ई-साइन अनुसार

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सा0) वनमण्डल खरगोन/संधवा,
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला बडवानी एवं जिला खरगोन अंतर्गत सोनखेडी तालाब योजना के निर्माण हेतु 49.320 हेक्टेयर (वनमंडल संधवा की 34.450 हे0 एवं वनमंडल खरगोन की 14.870 हे) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/155614/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 10.06.2025

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने से vi बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है।

- I. The State Government shall furnish a comprehensive report indicating the impact of the proposed project on downstream flow of water.
- II. The proposed diversion of forest land is located within a distance of 6.51 km from Yawal Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra. Therefore, the comments and clear recommendations of the Chief Wildlife Warden (CWLW), shall be submitted.
- III. The proposed project is located within 0.50 km of the inter-state boundary with Maharashtra, and a portion of the canal alignment lies in close proximity to this border. In view of the possible downstream and inter-state implications of the project, the State Government shall obtain and submit the "No Objection Certificate" from the Government of Maharashtra.
- IV. The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects wrt the safety of the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions.
- V. Further, the State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State Dam Safety Organisation (SDSO) and submit the same.
- VI. The details about the command area, irrigation potential, present cropping pattern, total population of the villages to be benefitted and the likely impact of the project on cropping pattern in future is essential for evaluating the socio-economic benefits of the project. The State shall submit a detailed report on these aspects.

अतः उपरोक्तानुसार लेख है, कि प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाही गयी जानकारी तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस.मोहन्ता)**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल**

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश
2. वनमण्डलाधिकारी, (सा0) वनमण्डल खरगोन/संधवा/बडवानी, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बडवानी, जिला बडवानी, म०प्र०।

की ओर सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।